© 2018 IJSRSET | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

21वीं सदी के उपन्यासों में ग्रामीण समाज पर कृषि का प्रभाव

संजय कुमार
(शोध छात्र), हिन्दी–विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

भारत देश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे हमारे देश में कृषि संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत देश की 51 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है अधिकांशतः ग्रामीण समाज के लोग निवास करते हैं जिनका जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संयुक्त परिवर टूट कर एकल परिवार में बदला और जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर मकान बनाकर रहने के लिए विवश हो गया। इस कारण प्रतिव्यक्ति जो भूमि उपलब्ध थी वह अब निरन्तर कम होती जा रही है। अभी भी कुछ लोगों के पास 25–30 (पच्चीस–तीस) बीघे जमीन है तो वही छोटे किसानों के पास एक से तीन बीघे तक और कुछ किसानों के पास जमीन ही नहीं है वे बड़े काश्तकारों के जमीन पर मजदूरी के रूप में काम करते हैं जिससे उनका जीवन–यापन बड़ी कठिनाई से चलता है इस कारण वे विवश होकर गाँव से शहर की तरफ पलायन कर रहे है। गाँवों में मजदूर न मिलने के कारण कृषि संकट उत्पन्न हो जाता है। 21 वीं सदी के कृषि संकट और ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण रामधारी सिंह 'दिवाकर' के उपन्यास 'अकाल संध्या' में देखने को मिलता है जहाँ बिहार के लोग अर्थिक रोजगार की तलाश में गाँव से शहर पलायन कर रहे हैं। ''दिल्ली, पंजाब हरियाणा से लेकर जम्मू तक काम की तलाश में निकलने वाले इन मजदूरों के कारण गाँव की कृषि व्यवस्था चरमरा गई है।''[1]

कृषि संकट और ग्रामीण समाज के लिए प्राकृतिक आपदायें भी कृषि संकट के लिए कारक है। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, अकाल एवं सूखा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आदि के कारण से फसलों और उपजाऊ मिट्टी का क्षय हो जाता है। इस प्रकार की समस्या किसानों के लिए आज भी बनी हुई है। खेती पर ग्रामीण समाज पूरी तरह से निर्भर रहता है फसलों के बर्बाद होने के कारण लोग भुखमरी का शिकार होने लगे है उनके पास इतना धन नहीं की वे अनाजों का क्रय करके अपने परिवार का भरण–पोषण सुचारू रूप से कर सके। 'कोसी नदी' जिसे बिहार राज्य का 'शोक' कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़

आती है जिससे वहाँ नदी के आस–पास के इलाके एवं फसले प्रभावित होती है। भूमि की उपजाऊ परत भी नदी की बाढ़ के साथ बह जाती है और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों में बीमारी और महामारी फैल जाती है इस कारण से वहां का जीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो जाता है। यह बिहार ही नहीं पूरे देश में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समस्या है। इस त्रासदी पर कई उपन्यासों में चर्चा हुई है। वर्तमान में कोशी नदी के बाढ़ की समस्या पर 'पुष्यमित्र' का उपन्यास 'रेडियों कोसी' में पुष्यमित्र ने इस समस्या को उजागर किया वहां आज भी 18वीं सदी जैसे हालात मौजूद हैं न बिजली, न स्कूल, न अस्पताल, न थाना है। 21वीं सदी की बाढ़ के यथार्थ का सजीव चित्रण पुष्यमित्र ने अपने उपन्यास के माध्यम से किया है। अकाल और सूखे के कारण कृषि संकट उत्पन्न हो रहे हैं पंजाब प्रान्त के किसान इस कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे है एवं ग्रामीण किसानों को जलवायु परिवर्तन की न समझ से फसल बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में 'फसल बीमा योजना' की नीति 13 जनवरी 2016 को चलायी गयी। इसमें किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होगा। इसके लिए मानक निर्धारित किया गया है कि खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। इस नीति के लागू होने से भी किसानों को लागत की भरपाई नहीं हो पाती और छोटे किसानों को इससे कोई लाभ नहीं मिल पाता जिससे किसानों को कृषि संकट की समस्या बनी रहती है।

आज जल कृषि और मनुष्य दोनों के लिए उपयोगी है। निरन्तर भूमि में पानी की कमी के कारण समाज और कृषि दोनों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही। भूमिगत जल का निरंतर दोहन होने से आज के समय में भूमिगत जल की कमी पैदा होती चली आ रही है। जिस कारण से लोगों को नहरों, नदी आदि पर निर्भर होना पड़ रहा है। नहरों और तालाबों में समय से पानी न मिलने पर फसल प्रभावित हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में कही–कहीं पर अधिकांशतः नहर व नदी न होने के कारण उन्हें भूमिगत जल द्वारा सिचाई करनी पड़ती है। जिस कारण से ग्रामीण लोगों को पेयजल और कृषि संकट दोनों ही समस्या का सामना करना पड़ता है। 21वीं सदी के उपन्यास 'कुइयाँजान' (2005) में 'नासिरा शर्मा' ने जल समस्या को प्रस्तुत किया है जिसमें निरन्तर भूमिगत जल के दोहन के विषय में 'नासिरा शर्मा' ने लिखा है कि ''हमने धरती से पानी तो खूब लिया, मगर उसे जो देना था वह नहीं दिया। इस धरती पर हुये हमारे अत्याचार ही हमें आज इस दुर्दशा में डाले हुए हैं। फिर भी हम होश में नहीं आ रहे। पहले धर्म को लेकर धर्म युद्ध होते थे फिर सीमा को लेकर तलवारे खिंचती थी और देखना कुरैशी भाई, जल

को लेकर प्रांतो के बीच युद्ध छिड़ेगा। ताज्जुब नहीं कि यह गृह–युद्ध एक दिन विश्व महायुद्ध में बदल जायेगा।''[2] कहीं–कहीं पर नम भूमि, निम्न जल स्तर एवं तेज ढलान के कारण खेती करने में कठिनाई होती है– ''उत्तर बिहार का मैदानी भाग, दक्षिण बिहार का मैदानी भाग और छोटा नागपुर या पठारी क्षेत्र पहला हिस्सा जो नदियों के साथ आयी मिट्टी से बना है और नेपाल के तराई वाले इलाकों से लेकर गंगा के उत्तरी किनारे तक आता है। यहां की जमीन उर्बरा और घनी आबादी वाली है। दक्षिण का मैदानी इलाका गंगा के दक्षिण तट से लेकर छोटा नागपुर के पठारों के बीच स्थित है, यहां सोन, पुनपुन, मोरहर, मुहाने, गामिनी नदियाँ है जो गंगा में जाकर मिलती है। बरसात में सारी नदियाँ उफनने लगती है। गंगा के मैदानी इलाके दक्षिणी भाग में पुराना पटना, गया और शाहाबाद जिलों तथा दक्षिणी मुंगेर और दक्षिणी भागलपुर आता है। जहां की जमीन में नमी बनाये रखने की क्षमता कम है। यहां भू जल स्तर बहुत कम है। गंगा के किनारे के इलाके को छोड़ कही भी कुआं या नलकूप खोदना असम्भव है। यह भू–भाग दक्षिण से उत्तर की तरफ तेज ढलान वाला है जिसके कारण धरती पर पानी का टिकना मोहाल है सो जलवायु खेती के अनुकूल नहीं है।''[3] वहीं भूमिगत जल के अत्याधिक दोहन से कुएं, नलकूप, सब सूख जा रहे है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से कुएं, नलकूप, सब सूख जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जल स्तर नीचे चला गया है वहाँ पर ग्रामीणों और कृषि के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। इस तरह देखा जाए तो 21वीं सदी के दूसरे दशक में दो तिहाई नदियां सूख गई है और जो बची है वह प्रदूषित हो गई है जिस कारण से सिंचाई एवं पेजयल की समस्या उत्पन्न हो रही है।

भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि संकट और ग्रामीण समाज पर प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में जो कृषि योग्य भूमि थी उनका अधिग्रहण कर औद्योगिक इकाईयाँ लगायी जा रही है तथा सड़के, रेलवे लाइन, पुल आदि का निर्माण किया जा रहा है। इससे कृषि योग्य भूमि कम होती चली जा रही है। कितने ग्रामीण लोग तो घर से बेघर तक हो जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों को मुआवजें के रूप में सरकार जो धन देती थी वह जमीन के लागत से कम होती थी। जिससे वे न हो तो खेती के लिए जमीन खरीद सकते थे और न घर। उन्हें शहरी जमीन की कीमत से कम धन दिया जाता था जिससे उनके लिए कृषि और आवास संकट दोनों उत्पन्न हो जाते थे। परन्तु आज के समय में केन्द्र सरकार ग्रामीणों की जमीन पर शहरी जमीन की कीमत से 6 गुने पर मुआवजा दे रही है। परन्तु कृषि संकट और आवास की समस्या तब होती है जब कृषि योग्य भूमि पर औद्योगिक इकाईयाँ लगने के कारण कृषि योग्य भूमि अब कम होती चली जा रही है। 'रणेन्द्र' ने 'ग्लोबल गांव के देवता' मैं भूमि अधिग्रहण जैसी समस्या को उठाया है जिससे

आज के समय में होने वाली कृषि संकट और ग्रामीण जीवन दोनों को प्रभावित कर रहा है। 'रैयती जमीन कम्पनियों को नहीं देनी है। नहीं तो धीरे–धीरे पाट पर खेती तो छोड़िये, रहने और पैर धरने को जमीन नहीं बचेगी। अबकी बार असुर कहाँ जायेगें?''[4]

इसी प्रकार भूमि ही नहीं नदी के जल का भी अधिग्रहण किया जा रहा है पानी जैसे साधनों के प्रयोग पर रोक लगा दी जा रही है और इस कारण से कृषि और व्यवसाय ग्रामीण समाज के लिए समस्या बनती जा रही है इसका जीता–जागता चित्रण 'कमल कुमार' के उपन्यास 'पासवर्ड' में छत्तीसगढ़ को नदी शिवनाथ नदी का नदी जल अधिग्रहण होता है जिस पर कमल कुमार ने लिखा है– ''एक और घटना हुई छत्तीसगढ़ में वहां की शिवनाथ नदी का निजीकरण हो गया । पता तब चला जब नदी के तेइस किलोमीटर के हिस्से के आस–पास रहने वाले लोगों को पानी के साधनों के प्रयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुबंधकर्ता कम्पनी और छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास निगम के बीच समझौते की जाँच के तथ्य आश्चर्यचकित हैं, आपत्तिजनक और अवैधानिक है। एक कुटिलतापूर्ण षड़यंत्र है। इस क्षेत्र में नदी के किनारे बसे मछुआरों की आबादी है। उनका व्यवसाय खत्म हो गया। वहां के निवासियों के प्रति पानी की आपूर्ति जिम्मेदारी किसकी है।''[5]

वर्तमान समय में किसानों की न समझ आपदाओं एवं सरकार द्वारा औद्योगिकरण के चलते जमीनों का अधिग्रहण, नदी जल अधिग्रहण के कारण कृषि संकट की समस्या बनी हुई है। दिनों–दिन किसानों के हालात खराब होते जा रहे है। जिससे कृषि और ग्रामीण जीवन पर इसका असर पड़ रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. रामधारी सिंह दिवाकर – अकाल संध्या, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ0सं0–97
2. नासिरा शर्मा – कुइयांजान, नई दिल्ली–सामयिक प्रकाशन संस्करण 2009, पृ0सं0–85
3. नासिरा शर्मा– कुइयांजान, नई दिल्ली–सामाजिक प्रकाशन संस्करण 2009, पृ0सं0 384
4. पुष्पपाल सिंह – 21वीं शती का हिन्दी उपन्यास, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ0सं0–90
5. कमल कुमार – पासवर्ड, सामयिक प्रकाशन पृ0सं0–63